>

Title: Need to give a share of revenue collected from rural areas to Panchayats for the development of the villages.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : आजादी से पहले भारत के नेताओं का एक सपना था कि भारत गांव में बसता है और अगर गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। धार्मिक दÂिष्ट से भी धार्मिक नेताओं ने भगवान को पाने के लिए गांव को ही केन्द्र माना लेकिन आजादी के बाद शायद हम सब गांव के विकास को भूल गये बहुत सी योजनायें भी जिन पर करोड़ों रूपये खर्च किये गये हैं, वे भी गांव का मूलभूत ढांचा सुधार नहीं कर पाये। गांव से शहर को पलायन बढ़ा है जिसका कारण रोजगार की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का कम होना, बिजली पानी जैसी समस्याओं का आज भी गांव में व्याप्त होना है। अगर गांव को आर्थिक तौर पर मजबूत कर दिया जाये और गांव की आमदनी का साधन बना दिया जाये तो गांव अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा। जैसे जो भी राजस्व एक गांव से मिलता है उस राजस्व की निश्चित मात्रा उसी गांव को दे दी जाये एवम् पंचायत के पास एक साल में कितना पैसा आने वाला है, वह हिसाब उनके पास रहेगा। उदाहरण के तौर पर किसी गांव में बिजली, टेलीफोन बिल, मार्किट फीस इत्यादि इकट्ठे होते और वह पैसा राज्य या केन्द्र के पास चला जाता है। अगर पहले सारा पैसा सरकार को जाये फिर वह पैसा वापिस गांव को जाये इस आने जाने से लिकेज् बहुत होती है अगर उस पैसे का प्रतिशत यहीं हर गांव को दे दिया जाये तो गांव की एक निश्चित आमदनी हो जायेगी। हर समय उस गांव को विकास के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह गांव में ईट के भट्टे लगते है, पैट्रोल पम्प होते है, शराब के ठेके खुलते है या कोई उद्योग लगता है उससे जो भी कर एकत्रित हो उसका एक निश्चित प्रतिशत वहीं गांव को दे देना चाहिए। इससे गांव आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। इससे विकास होगा। रोजगार के साधन पैदा होंगे और पंचायती राज प्रणाली मजबूत होगी। आशा है कि सरकार इस विषय को ध्यान में रखते हुए योजना मेरे इस बिन्दु को ध्यान में रखकर बनायेगी।